भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2155

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

विधि प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण

2155. श्री नायब सिंह सैनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समाज के कमजोर वर्ग को लाभ प्रदान करने के लिए टेली-लॉ पहल/योजना के तहत अधिवक्ताओं और विधि के छात्रों की विशेषज्ञता का उपयोग करने का विचार है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के पास न्याय परिदान प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षुता पूरा करने वाले विधि के छात्रों को शामिल करने की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) ऐसे विधि प्रशिक्षुओं की प्रतिभा और अनुभव का उपयोग करने के लिए सरकार की अन्य क्या विशिष्ट योजना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार अपने टेली-लॉ पहल के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध टेली-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के द्वारा पैनल वकीलों के एक काडर माध्यम से और नागरिकों के 'टेली-लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पूर्व-मुकदमा सलाह और परामर्श प्रदान करती है। अब तक टेली-लॉ के अधीन अब तक 854 पैनल वकीलों को सम्मिलित किया गया है। टेली-लॉ के अधिकतम फायदो को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए, विशेष रूप से विधि के छात्रों और

सामान्य रूप से छात्रों को स्वयंसेवा करने और नागरिकों के टेली-लॉ मोबाइल ऐप पर परा विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

(ग) से (ङ) : जी, हां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) वर्ष की ग्रीष्म कालीन और शीत कालीन अवधि के दौरान विधि के छात्रों के लिए 3 सप्ताह का प्रशिक्षुता कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षुता कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि विधि इंटर्न को क्षेत्रीय केंद्र बिंदु के साथ विधिक सेवा संस्थानों और विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्य करने का एक व्यापक विचार मिलता है। इस प्रशिक्षता के दौरान छात्र केंद्रीय जेल या उप जेल जाते हैं और कैदियों के साथ बातचीत करते हैं जिससे पता लगाया जा सके कि उनका प्रतिनिधित्व काउंसिल कर रहे हैं और कैदियों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं, विधिक सेवा क्लीनिक के कार्य करने का संप्रेक्षण करते हैं, संप्रेक्षण गृह/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/औषध पुनर्वास केंद्र/जिला न्यायालय जिसमें मजिस्ट्रियल, सत्र और सिविल न्यायालय और पुलिस स्टेशन सम्मिलित हैं और इन संस्थानों में विधिक सेवा वकीलों की भूमिका को देखें। छात्र विधिक साक्षरता/विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में भी उपस्थित होते हैं और उनमें भाग लेते हैं। प्रशिक्षुता के सफल समापन पर विधि इंटर्न को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

****